ECONOMIC TIMES, Delhi, 17.9.2023
Page No. 7, Size:(8.03)cms X (16.18)cms.

BP CEO Search is Big Oil's Best Chance to Fix its Gender Problem

Big oil has yet to appoint its first female CEO – something BP could soon change

Bloomberg

Titans of the oil and gas world like Exxon Mobil, Chevron, Shell, and BP have successfully adapted to countless societal changes over the last century — war, nationalisations, even the climate movement. But a major hurdle remains: Big oil has yet to appoint its first-ever female chief executive — something BP could soon change.

This week, the 114-year old British oil company parted ways with its CEO Bernard Looney after multiple investigations found he failed to disclose several workplace relationships. What the board knew and when remains unclear.

Appointing a female CEO would send a clear message that the clubby era of petro-masculinity could finally be coming to an end. But doing so will require bucking more than a century of precedent: Only two women — Vicki Hollub at Occidental Petroleum and Meg O'Neill at Woodside Energy Group — currently lead large international oil companies.

"It's a very tough culture," Jane Stevenson, global leader for CEO succession at executive search firm Korn Ferry, said.

In the US, women represent just 13% of the oil and gas C-suite, the lowest of any professional industry, according to McKinsey & Co.

Worldwide, women occupy just 22% of jobs in oil and gas, making it the third-most gender imbalanced industry, according to a 2021 study by Boston Consulting Group and the World Petroleum Council.

In BP, women make up 39% of employees and 30% of senior leaders, both higher than before the pandemic

To explain the disparity, industry executives often point to the dearth of women studying science, technology, engineering and math. But this only accounts for part of the problem: While women earned only 22% of degrees in engineering in 2018, they earned 53% of STEM degrees, according to Pew Research. In the BCG study, the top two career obstacles women cited were not being told of job opportunities and unfair performance evaluations.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 17.9.2023
Page No. 4, Size:(15.39)cms X (5.69)cms.

CRUDE WATCH

OIL PRICES HIT 10-MONTH HIGH

Oil prices hit a 10-month high on Friday and posted a third weekly gain as supply tightness spearheaded by Saudi Arabian production cuts combined with optimism around Chinese demand to lift crude. **REUTERS**

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 17.9.2023
Page No. 8, Size:(2.54)cms X (10.13)cms.

एलपीजी प्लांट में गैस पाइप लाइन में रिसाव की मॉक ड्रिल

गुरुग्राम, 16 सितंबर (हप्र)

जिला प्रशासन व एनडीआरएफ (नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) द्वारा भोंडसी क्षेत्र के नया गांव स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में गैस पाइप लाइन रिसाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन तैयारी की जांच किए जाने के लिए यह ऑफ साइट इमरजेंसी ड्रिल थी।

इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने पाइप लाइन गैस रिसाव होने की स्थिति में वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के तौर तरीकों के बारे में बताया। वहीं मॉक ड्रिल के बाद कमियों एवं त्रुटियों की चर्चा के लिए समीक्षा बैठक भी की गई।

ऑफ साइट इमरजेंसी ड्रिल के तहत नयागांव में इंडियन ऑयल की एलपीजी गैस पाइप लाइन लीक हो गई। गैस रिसाव के बारे में तुरंत बाद लाइनमैन ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। वहां से इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल तत्काल इंजीनियरों की टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उसके बाद एनडीआरएफ द्वारा गैस रिसाव से संबंधित आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल देखने को मिली।

दैनिक ट्रिब्यून

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 17.9.2023
Page No. 15, Size:(4.18)cms X (12.78)cms.

घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा, डीजल पर शुल्क में कटौती

नई दिल्ली। सरकार ने कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति टन कर दिया। यह 16 सितंबर से प्रभावी होगा। इससे पहले, एक सितंबर को पाक्षिक समीक्षा में देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 6,700 रुपए प्रति टन तय किया गया था। सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 5.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। फिलहाल यह छह रुपए लीटर है। विमान ईंधन यानी एटीएफ पर शुल्क को घटाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है जो वर्तमान में चार रुपए लीटर है। सूत्रों ने बताया कि पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य बना रहेगा। संशोधित दरें शनिवार से लागू होंगी। देश में अप्रत्याशित लाभ पर कर सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को लगाया गया था।

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 17.9.2023
Page No. 15, Size:(8.63)cms X (14.84)cms.

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीं

एजेंसी ■ इस्लामाबाद

पाकिस्तान में मुद्रास्फीति के दहाई अंकों में पहुंच जाने के बीच कार्यवाहक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। इन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। कार्यवाहक सरकार के इस फैसले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे दी गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार रात पेट्रोल की कीमत में 26.02 रुपए और डीजल की कीमत में 17.34 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमतें 330 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई हैं। इसके पहले एक सितंबर को भी कार्यवाहक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। पिछले महीने देश में कार्यवाहक सरकार बनने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम 20 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में 15 अगस्त के बाद से पेट्रोल की कीमत में 32.14 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 38.49 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। समाचार-पत्र डॉन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का 330 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचना एक मनोवैज्ञानिक अवरोध के टूटने जैसा है। अगस्त में मुद्रास्फीति की दर 27.4 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद विपक्षी दल जहां इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

NAVODYA TIMES, Delhi, 17.9.2023
Page No. 8, Size:(14.47)cms X (8.27)cms.

पैट्रोलियम पदार्थों में लोगों को राहत दे सरकार

राजनीतिक कुशलता कहें, लोगों से सीधे संवाद बनाने की भावुकता कहें या निरा जुबान फिसलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐसी बात बोल जाते हैं जो कभी-कभी उनको ही उलटी पड़ जाती है। अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए उन्होंने पैट्रोलियम पदार्थों का दाम कम होने की चर्चा के संदर्भ में खुद को भाग्यशाली और शासक के साथ प्रजा का भाग्य चलने वाली लोकोक्ति तो सुनाई पर अपने ही पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह को अभागा भी कह दिया।

हम जानते हैं कि मनमोहन राज के बाद के समय में पैट्रोलियम पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सौ सवा सौ डालर प्रति बैरल के बीच ही झूलता रहा और मनमोहन सरकार को तेल की कीमतों को संभालने में काफी द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ा। मोदी के आते ही कीमतें गिरने लगीं और एक बार तो ऋणात्मक हो गई थीं। जब वे यह भाषण दे रहे थे तब संभवत: कीमतें 25 डालर के आसपास थीं और इसे संयोग और खुशनसीबी से जोड़ने की कोई खास वजह नहीं है।

कीमतों के उतार-चढ़ाव की पचासों ठोस वजहें होती हैं। पर अब दूसरे कार्यकाल के बाद होने वाले आम चुनाव का सामना करते समय मोदी को अपना वह भाषण याद हो न हो (वैसे वे कोई बात आसानी से भूलते नहीं) पत्रकारों को वह भाषण याद आ रहा है।

इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में फिर आग लगना है। कीमतें 90 डालर प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं और उनका रुख पिछले महीनों से ऊपर की तरफ ही है। इसकी वजह कोविड के बाद उद्योग-धंधों का कामकाज पटरी पर लौटना और तेल की मांग बढ़ना है और मोदी की और परेशानी की वजह इस बीच रुपए की कीमत का रिकार्ड नीचे हो जाना भी है।

अरविन्द मोहन

मनमोहन राज की तुलना में तो डालर आसमान पर पहुंच गया था और अगर उस आधार पर गिनती की जाए तो मामला तब से ऊपर कीमत का बन चुका है। लेकिन 2 बातों में स्थिति अलग है। एक तो इस बीच तेल कंपनियां कमाकर मोटी हो चुकी हैं। यह अलग बात है कि अब उनका लाभ खत्म-सा है सो उन पर दबाव डालकर सरकार कीमत नियंत्रित करने की नहीं सोच सकती।

सरकार ने भी इन 9 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरावट का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं जाने दिया और उत्पाद शुल्क से लेकर दूसरे छोटे-बड़े करों के सहारे हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा लिया। अब वह अपने और राज्यों के कर का एक हिस्सा कम करके आम ग्राहकों को पैट्रोलियम की ज्वलनशीलता से कुछ राहत दे सकती है पर इस उपाय की भी सीमा है।

यह सीमा रसोई गैस के मामले में तुरंत दिखने भी लगी है जहां प्रति सिलैंडर 200 रुपए की कटौती (जिसे कई सारे लोग आगामी चुनावों से जोड़कर देखते हैं पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे रक्षाबंधन का तोहफा बताया) तो हो गई लेकिन महीनों से रुकी पैट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई कटौती या बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल अब कीमतें गिरने वाला दौर तो खत्म हो गया है। अगर सरकार को कीमतें नीचे लानी हैं तो उसे अपने खजाने में रोज करों में कटौती करनी होगी और पहले से तंग हाथ को और कसना पड़ेगा।

चुनाव के वक्त ऐसा करना भी मुश्किल है और गैस के बाद पैट्रोल-डीजल को अछूता छोड़ना भी बल्कि लोग मानते हैं कि सरकार को तेल के साथ मिलने वाले अतिरिक्त कर राजस्व का ऐसा चस्का लगा है कि आने वाले काफी समय तक उसमें कटौती मुश्किल है और अगर ऐसा किया भी गया तो मामूली कटौती ही संभव है। अगर केंद्र के हाथ बंधे हैं तो राज्य सरकारों के भी कोई खुले नहीं हैं और वे अपने कर कम करके राहत दें यह भी संभव नहीं लगता है।

केंद्र के लिए राहत की एक बात तो रूसी तेल का आयात बढ़ना है। हमको रूस का तेल जिस कीमत पर मिल रहा था और अब जिस कीमत पर मिल रहा है उसमें फर्क है, लेकिन वह अब भी सस्ता है। शुरू में भारत के आयात का पश्चिम के देशों ने शोर मचाया लेकिन बाद में पता चला कि अमरीका सहित सभी यही धंधा कर रहे हैं और रूस अपने तेल भंडार खाली करके लड़ाई में पैसे झोंके जा रहा है। पर भारत के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ इस तरह भी हो गया कि भारत ने रूसी तेल को परिशोधित करके उसका कुछ हिस्सा बाजार दर पर निर्यात भी कर दिया। पर कीमतें बढ़ने का असर सरकार पिछले कुछ समय से महसूस कर रही है।

पैट्रोल से मिलने वाला कर राजस्व अब 2020-21 और 2021-22 के करीब 4 लाख करोड़ से गिरकर सवा 3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यह गिरावट लगभग 20 फीसदी है जबकि उपभोक्ताओं की नाराजगी भी बनी ही हुई है।

तत्काल तो 5 राज्यों के चुनाव हैं लेकिन लोकसभा चुनाव के बादल भी आसमान पर दिखने लगे हैं और तेल के कारोबार पर नजर रखने वाले सभी जानकारों का मानना है कि हाल फिलहाल कीमतों के टूटने के आसार नहीं हैं। सैंटर फार मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जुटाए आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले नवंबर से तेल की कीमतें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं।

हमारा उपभोग भी बढ़ता जा रहा है और इन दोनों के निकट भविष्य अर्थात मई 2024 तक बहुत नीचे आने के लक्षण नहीं हैं। इसलिए मोदी सरकार को सावधान करना बनता है कि सावधान पैट्रोलियम ज्वलनशील पदार्थ है। हैंडल विद केयर।

arvindmohan2000@yahoo.com

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 17.9.2023
Page No. 7, Size:(5.21)cms X (6.56)cms.

सीएनजी पंप लगाने के नाम पर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से 3 लाख ठगे

रेवाड़ी, 16 सितंबर (हप्र)

सीएनजी पंप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर को उस समय महंगा पड़ा गया, जब साइबर ठग ने उनके साथ 3 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर डाली।

शक्ति नगर में रहने वाले सुरेंद्र कुमार मूलरूप से महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और और कुछ दिन पूर्व ही रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने अडाणी गैस प्रा. लि. कंपनी में सीएनजी पंप के लिए जून माह में ऑनलाइन साइट पर अप्लाई किया था। 6 जून को उनके पास किसी ने कॉल की और कहा कि उनका आवेदन मिल गया है। कॉलकर्ता ने उससे आधार कार्ड के नंबर पूछे। अगले दिन फिर एक कॉल आई और कहा कि ई-मेल पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वे ई-मेल पर ही भेज दें। सुरेंद्र ने कहा कि उसने मेल के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड व 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भेज दिया। कॉलकर्ता ने पंप के लिए फीस के तौर पर एक्सिस बैंक के जरिए 52800 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से अपने खाते में डलवाए। फिर अलग-अलग समय कुल 3 लाख रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर करवा ली। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह अहमदाबाद स्थित अडाणी गैस के कार्यालय पहुंच गए। वहां पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उनकी कोई ऐसी साइट नहीं है।

दैनिक ट्रिब्यून Sun, 17 September 2023
https://epaper.dainiktribu